भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2377

दिनांक 13 फरवरी, 2026 को उत्तर के लिए

पोषण ट्रैकर का उपयोग

2377. श्री सी.एन. अन्नादुरई:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तमिलनाडु ने पोषण 2.0 के तहत बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए बौनापन, दुबलापन और एनीमिया जैसे संकेतकों के संबंध में निरंतर सुधार को प्राप्त किया है;

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्य में दर्ज किए गए पोषण परिणामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या तमिलनाडु में लाभार्थियों की वास्तविक समय निगरानी के लिए 'पोषण ट्रैकर' के प्रभावी उपयोग ने सेवा वितरण और जवाबदेही को मजबूत किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) को दूर करने के लिए किए गए गहन पोषण हस्तक्षेपों के परिणामस्वरूप मापने योग्य सुधार हुए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार राष्ट्रीय पोषण संकेतकों में सुधार के लिए अन्य राज्यों में बौनेपन/दुबलेपन के स्तर को कम करने में तमिलनाडु की सर्वोत्तम प्रथाओं को लागू करने पर विचार कर रही है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री
(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): मंत्रालय का पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन, मिशन पोषण 2.0 के तहत आंगनवाड़ी केंद्रों में आने वाले या घर पर आंगनवाड़ी सेवाएं प्राप्त करने वाले उन बच्चों का डेटा प्रदान करता है, जिनमें उनके कुपोषण के संकेतकों (ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन) की जानकारी भी शामिल है। पोषण ट्रैकर डेटा से पता चलता है कि तमिलनाडु ने बाल कुपोषण को कम करने में लगातार सुधार हासिल किया है। तमिलनाडु राज्य के लिए मिशन पोषण 2.0 के पोषण संबंधी परिणामों, सुदृढ़ सेवा प्रदायगी और अन्य घटकों का विवरण https://www.poshantracker.in/statistics पर उपलब्ध है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) के अनुसार, तमिलनाडु राज्य में बच्चों (0-5 वर्ष) में एनीमिया का प्रसार 57.4 प्रतिशत है।

पोषण ट्रैकर एप्लिकेशन को मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण शासन उपकरण के रूप में लॉन्च किया गया है। इस एप्लिकेशन के तहत तकनीक का उपयोग बच्चों में ठिगनापन, दुबलापन और कम वजन की व्याप्तता की सुलभ पहचान के लिए किया जा रहा है। इसने आंगनवाड़ी सेवाओं जैसे कि आंगनवाड़ी केंद्रों का खुलना, बच्चों की दैनिक उपस्थिति, ईसीसीई गतिविधियां, बच्चों की वृद्धि निगरानी, पका हुआ गर्म भोजन (एचसीएम)/घर ले जाने वाला राशन (टीएचआर) का प्रावधान, वृद्धि मापन इत्यादि के लिए लगभग तत्समय में डेटा संग्रह को सुगम बनाया है। पोषण ट्रैकर के प्रभावी उपयोग ने देश भर में मिशन पोषण 2.0 के तहत लाभार्थियों की तत्समय निगरानी, सेवा प्रदायगी और जवाबदेही को सुदृढ़ बनाया है। गंभीर तीव्र कुपोषण (एसएएम) और मध्यम तीव्र कुपोषण (एमएएम) से निपटने के लिए की गई पोषण पहलों के कारण हुए मापनीय सुधारों को https://www.poshantracker.in/statistics पर देखा जा सकता है।

मिशन पोषण 2.0 के अंतर्गत सामुदायिक सहभागिता, जनसंपर्क (आउटरीच), व्यवहार परिवर्तन तथा जन-जागरूकता जैसी गतिविधियों के माध्यम से कुपोषण में कमी लाने तथा स्वास्थ्य, कल्याण एवं रोग प्रतिरक्षा में सुधार हेतु एक नई कार्यनीति अपनाई गई है। यह मिशन विशेष रूप से मातृ पोषण, शिशु एवं छोटे बच्चों के आहार मानकों, गंभीर तीव्र कुपोषण एवं मध्यम तीव्र कुपोषण के उपचार तथा आयुष पद्धतियों के माध्यम से स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है, ताकि ठिगनापन, दुबलापन, एनीमिया तथा कम वजन की व्यापतता को कम किया जा सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में निहित पोषण मानदंडों के अनुसार, 6 महीने से 6 वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 14-18 वर्ष की किशोरियों को पूरक पोषण प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, सूक्ष्म पोषक तत्वों की आवश्यकता को पूरा करने और महिलाओं एवं बच्चों में एनीमिया को कम करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति की जा रही है। आंगनवाड़ी केंद्रों में पका हुआ गर्म भोजन और घर ले जाने वाले राशन की तैयारी में सप्ताह में कम से कम एक बार मिलेट (श्री अन्न) के प्रयोग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कुपोषित बच्चों के प्रबंधन और इससे संबंधित रुग्णता और मृत्यु दर को कम करने के लिए संयुक्त रूप से 'बच्चों में कुपोषण प्रबंधन प्रोटोकॉल' जारी किया है। आहार विविधता और स्थानीय पौष्टिक उत्पादों के सेवन को प्रोत्साहित करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषण वाटिकाएं विकसित की गई हैं। मिशन के अंतर्गत प्रमुख गतिविधियां सामुदायिक जुटाव और जागरूकता अभियान हैं, जिनका उद्देश्य लोगों को पोषण संबंधी पहलुओं के बारे में शिक्षित करना है, क्योंकि पोषण की अच्छी आदत अपनाने के लिए व्यवहार परिवर्तन हेतु निरंतर प्रयासों की आवश्यकता होती है। पोषण माह, पोषण पखवाड़ा और मासिक सामुदायिक आधारित कार्यक्रमों (सीबीई) के दौरान जन आंदोलन के माध्यम से यह जागरूकता अभियान सुनिश्चित किया जा रहा है।

मिशन पोषण 2.0 के तहत, गंभीर कुपोषण से पीड़ित बच्चों को टेक-होम राशन (टीएचआर) के रूप में अतिरिक्त पोषण प्रदान किया जा रहा है। तमिलनाडु सरकार ने बच्चों में कुपोषण को कम करने के लिए "उत्तचथाई उरुथी सेई" योजना को कार्यान्वित किया है। इस योजना के तहत, छह महीने से कम उम्र के कुपोषित बच्चों की माताओं को पोषण किट प्रदान की जाती हैं ताकि बच्चे की पोषण स्थिति में सुधार हो सके।

- गंभीर कुपोषित बच्चों की माताओं को दो पोषण किट दी जाती हैं।
- मध्यम रूप से कुपोषित बच्चों की माताओं को एक पोषण किट दी जाती है।

******